विषय-सूची

1. राजनीतिक प्रणाली, सरकारें एवं संविधान 1.1-1.19

राजनीतिक प्रणाली 1.1
अवधारणा 1.1
एक राजनीतिक व्यवस्था के उद्गम के कारक 1.1
राजनीतिक प्रणाली के रूप 1.1

सरकार एवं शासन 1.1
संविधान 1.2
अवधारणा 1.2

लोकतंत्र 1.2
उद्भव 1.2
समान सिद्धांतों से जुड़े विभिन्न लोकतांत्रिक रूप 1.2
लोकतंत्र क्यों 1.3
संयुक्त राष्ट्र एवं लोकतंत्र 1.3

प्रतिनिधि लोकतंत्र 1.3
संसदीय प्रणाली 1.3
प्रमुख विशेषताएं 1.3
संसदीय प्रणाली के गुण 1.4
संसदीय प्रणाली के दोष 1.4

अध्यक्षात्मक प्रणाली 1.5
प्रमुख विशेषताएं 1.5
अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण 1.6
अध्यक्षात्मक प्रणाली के दोष 1.6

संसदीय एवं अध्यक्षात्मक प्रणालियां: एक तुलना 1.7
भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 1.8
भारत का संविधान: एक दृष्टि में 1.9

2. ऐतिहासिक परिदृश्य 2.1-2.22

भारत में संवैधानिक विकास 2.1
संवैधानिक सरकार: भारत में आधुनिक विकास 2.1
कंपनी हेतु निर्मित कानूनों से क्षेत्र के लिए बनाए गए कानूनों में संक्रमण 2.1
कंपनी शासन—1765 से 1858 2.3
ब्रिटिश सम्राट/साम्राज्ञी का शासन—1858 से 1947 2.8

भारतीय शासन में ब्रिटिश विरासत 2.20
सरकार की प्रणाली 2.20
लोक प्रशासन व्यवस्था 2.21
विधि प्रवर्तन 2.22
आलोचना 2.22

3. संविधान का निर्माण 3.1-3.9

संविधान सभा का गठन 3.1
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 3.1
कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन 3.1

संगठन: प्रतिनिधि किस प्रकार संविधान सभा थे? 3.3
संविधान सभा का कार्यकरण 3.4
उद्देश्य प्रस्ताव 3.5
समितियों एवं सहमति के माध्यम से कार्य 3.5
संविधान निर्माण के अलावा अन्य कार्य 3.6

प्रारंभ की तिथि 3.7
संविधान सभा एक संसद भी 3.7

परिचर्चा

- क्या सभा संप्रभु थी? 3.8
- संविधान सभा पर कांग्रेस की संस्था बनने और हिंदू तथा अधिवक्ताओं के प्रभुत्व वाली संस्था होने का आरोप 3.8

4. संविधान की विशेषताएं एवं दर्शन 4.1-4.15

उल्लेखनीय विशेषताएं 4.1
भारी-भरकम लिखित दस्तावेज 4.1
विभिन्न स्रोतों का समावेश 4.1
नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय 4.2

धर्मनिरपेक्ष राज्य 4.2
सुदृढ़ केंद्र वाली संघीय व्यवस्था 4.2
संसदीय सरकार 4.2
स्थानीय सरकार को शक्ति हस्तांतरण 4.2
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार 4.3
स्वतंत्र समन्वित न्यायपालिका 4.3
मौलिक अधिकार 4.3
राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत 4.3
मौलिक कर्तव्य 4.3
अन्य विशेषताएं 4.3

प्रस्तावनाः संविधान का दर्शन 4.3
प्रस्तावना का पाठ 4.4
प्रस्तावनाः संविधान के दर्शन का सार 4.4
प्रस्तावना में समाविष्ट महत्वपूर्ण शब्दों का महत्व 4.4

संविधान के आलोचनात्मक बिंदु 4.8
विभिन्न संविधानों से बना संविधान 4.8
सर्वाधिक व्यापक लिखित संविधान 4.9
अधिवक्ताओं का स्वर्ग 4.9
वास्तविक रूप से भारतीय या गांधीवादी नहीं 4.9
1935 के अधिनियम का पुनर्निर्मित रूप 4.9
अन्य बिंदु 4.9

परिचर्चा

- क्या भारतीय संविधान 1935 के भारत सरकार अधिनियम का पुनर्लेखन है? 4.10
- भारत ने संसदीय प्रणाली क्यों अपनाई? 4.11
- भारतीय व्यवस्था ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? 4.11
- क्या भारत को अध्यक्षीय शासन प्रणाली में परिवर्तित होना चाहिए? 4.12
- क्या प्रस्तावना संविधान का एक भाग है और क्या यह परिवर्तनीय है? 4.13

5. संघ क्षेत्र एवं राज्यों का पुनर्गठन 5.1-5.12

संघ और उसका राज्यक्षेत्र 5.1
'राज्यों का संघ' शब्द का महत्व 5.1
राज्यक्षेत्र की श्रेणियां 5.1

नए राज्यों का निर्माण एवं पुनर्गठन 5.2
नवीन राज्यों का निर्माण 5.2
भारत के भीतर राज्यों का पुनर्गठन 5.2

नामों में परिवर्तन 5.6
जब भारतीय क्षेत्र अन्य देश को सौंपा गया या क्षेत्र की अदला-बदली की गई 5.7

परिचर्चा

- नवीन एवं छोटे राज्य—कितने व्यवहार्य? 5.8
- अधिकाधिक राज्यों की मांग के कारण 5.9
- छोटे राज्यों के गुण एवं दोष 5.9

6. नागरिकता 6.1-6.12

संवैधानिक प्रावधान 6.1
संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता 6.1
अन्य संवैधानिक प्रावधान 6.2

नागरिकता अधिनियम 1955ः नागरिकता पर संविधिक प्रावधान 6.2
नागरिकता का अर्जन 6.3
नागरिकता की समाप्ति 6.5

ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डहोल्डर 6.6
ओसीआई कार्डधारक हेतु प्रावधान 6.7
ओसीआई कार्डधारक का पंजीकरण 6.7
ओसीआई कार्डधारकों के अधिकार 6.7
ओसीआई कार्ड का परित्याग 6.8
ओसीआईसी के रूप में पंजीकरण का निरस्तीकरण 6.8
ओसीआईसीः दोहरी नागरिकता नहीं 6.8
एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई कार्डधारकों की तुलना 6.8

नागरिकता का महत्व 6.10
एकल नागरिकता 6.11
एकल नागरिकताः संघ की नागरिकता 6.11
एक देश की एकल नागरिकता 6.12

7. मौलिक अधिकार 7.1-7.36

अधिकारों की प्रकृति 7.1
राज्य का अर्थ 7.2
मौलिक अधिकारों से असंगत विधियां 7.2
न्यायिक समीक्षा की शक्ति 7.3
क्या अनुच्छेद 13 के अंतर्गत 'विधि' संवैधानिक संशोधन के विषयाधीन है? 7.3

वर्गीकरण 7.3
1. समानता का अधिकार 7.4
विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण 7.4
विधि का शासन 7.4
समानता के अपवाद 7.5
धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध 7.6
अपवाद 7.6
लोक नियोजन में अवसर की समानता 7.8
अपवाद 7.8
नौकरियों में ईडब्ल्यूएस हेतु आरक्षण के अपवाद 7.10
अस्पृश्यता का उन्मूलन 7.10
उपाधियों का अंत 7.11

2. स्वतंत्रता का अधिकार 7.12
छह स्वतंत्रताओं का संरक्षण 7.12
1. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 7.12
2. शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता 7.13
3. संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता 7.14
4. भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता 7.14
5. निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता 7.14
6. वृत्ति, व्यापार इत्यादि करने की स्वतंत्रता 7.15
अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण 7.15
कार्योत्तर विधि का प्रतिषेध 7.15
दोहरे दण्ड/अभियोजन से संरक्षण 7.16
स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण 7.16
प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 7.16
अनुच्छेद 21 का विस्तार 7.17
शिक्षा का अधिकार 7.19
गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण 7.19
साधारण विधि के अंतर्गत निरोध 7.20
निवारक निरोध का मुद्दा 7.20

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार 7.21
मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध 7.21
कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध 7.22

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 7.22
अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 7.22
धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 7.23
धार्मिक अभिवृद्धि हेतु करों के संदाय की स्वतंत्रता 7.24
धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने से स्वतंत्रता 7.24

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 7.24
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 7.24
अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासित करने का अधिकार 7.24

6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार 7.25
अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार 7.25

मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संसद की शक्ति 7.27
बलों आदि को लागू होने में अधिकारों का उपांतरण करने की संसद की शक्ति 7.27
सेना विधि के प्रवृत्त होने के दौरान अधिकारों पर निर्बन्धन 7.28
मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए विधान 7.28

कुछ विधियों की व्यावृत्ति 7.29
संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति 7.29
कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण 7.29
कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति 7.30

भाग III से बाहर अधिकार 7.30

परिचर्चा

- स्वतंत्रता के अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन 7.30
- सूचना का अधिकार 7.31
- संपत्ति के अधिकार का मामला 7.32

- मौलिक अधिकारों की संशोधनीयता 7.33
- क्या मौलिक अधिकार उपयोगी हैं? 7.34

8. राज्य के नीति निदेशक तत्व 8.1-8.11

सिद्धांतों की प्रकृति 8.1
निदेशक तत्वों का वर्गीकरण 8.1
समाजवादी विचारधारा को अभिव्यक्त करने वाले निदेशक तत्व 8.2
गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित 8.2
उदारवादी विचारधारा को परिलक्षित करने वाले निदेशक तत्व 8.2
निदेशक तत्वों का अवलोकन 8.2
संविधान के अन्य भागों में निदेश 8.3
क्रियान्वयन 8.3
नीति निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन हेतु उठाए गए कदम 8.4
टिप्पणी 8.5

परिचर्चा

- मौलिक अधिकार एवं निदेशक सिद्धांतः तुलना एवं पारस्परिक महत्व 8.6
- निदेशक सिद्धांत कितने महत्वपूर्ण हैं? 8.8

9. मौलिक कर्तव्य 9.1-9.8

एक नया विचार नहीं 9.1
मौलिक कर्तव्यों पर स्वर्ण सिंह समिति 9.2
संविधान में सूचीबद्ध मौलिक कर्तव्य 9.2
कर्तव्यों की प्रकृति 9.3
न्यायाधीश वर्मा समिति 9.3
मौजूदा वैधानिक प्रावधान 9.3
आगे की कार्रवाई हेतु सुझाव 9.3

परिचर्चा

- मौलिक कर्तव्यों की आलोचना 9.4
- मौलिक कर्तव्यों का महत्व 9.5
- मौलिक कर्तव्यों पर न्यायालय का संज्ञान 9.6
- क्या मौलिक कर्तव्य प्रवर्तनीय होने चाहिए? 9.7

10. संघीय कार्यपालिका 10.1-10.41

संघ एवं संघीय कार्यपालिका 10.1
राष्ट्रपति 10.1
निर्वाचन प्रक्रिया 10.1
निर्वाचक मंडल 10.2
मत का मूल्य 10.2
आनुपातिक प्रतिनिधित्व (या वैकल्पिक मत प्रणाली) 10.2
चुनाव संबंधी विवाद 10.3
पदावधि 10.3
निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं 10.4
पद हेतु शर्तें 10.4
शपथ या प्रतिज्ञान 10.4
महाभियोग द्वारा पद से हटाने की प्रक्रिया 10.4
रिक्ति 10.5
शक्तियां एवं कर्तव्य 10.6
राष्ट्रपति के विशेषाधिकार 10.8
उपराष्ट्रपति 10.8
निर्वाचन 10.9
निर्वाचन प्रक्रिया 10.9
निर्वाचन विवाद 10.9
उम्मीदवारों के लिए योग्यता 10.9
पदावधि 10.10
रिक्ति 10.10
शपथ या प्रतिज्ञान 10.10
शक्तियां एवं कार्य 10.10
वेतन और भत्ते 10.11
मंत्रिपरिषद 10.11
प्रधानमंत्री की नियुक्ति 10.11
मंत्रियों की नियुक्ति 10.12
शपथ या प्रतिज्ञान 10.12
मंत्रिपरिषद का गठन 10.12
वेतन 10.13
पदावधि 10.13
सामूहिक उत्तरदायित्व 10.13

व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 10.14
कानूनी उत्तरदायित्व 10.14
मंत्रिपरिषद की शक्तियां 10.14

मंत्रिमंडल 10.14
भारत में मंत्रिमंडल की भूमिका 10.15
मंत्रिमंडल किस प्रकार मंत्रिपरिषद से भिन्न है? 10.15
मंत्रिमंडलीय समितियां 10.16
मंत्रिमंडलीय समितियों का इतिहास 10.16
समितियों के प्रकार 10.17
मंत्रिमंडलीय समितियों के कार्य 10.17
मंत्रिमंडलीय समितियों के प्रमुख प्रयोग 10.17

ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एवं एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स 10.17

प्रधानमंत्री की स्थिति एवं भूमिका 10.18
प्रधानमंत्री की स्थिति 10.18
प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कृत्य 10.18
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद 10.18
प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति 10.19
प्रधानमंत्री एवं संसद 10.19

उप-प्रधानमंत्री 10.19

भारत का महान्यायवादी 10.20
नियुक्ति, पदावधि, अर्हताएं, वेतन 10.20
अधिकार एवं कृत्य 10.20
निर्बन्धन 10.20
महान्यायवादी एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 10.21

सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया 10.21

सरकार के मंत्रालय एवं विभाग 10.21

परिचर्चा

- भारत के राष्ट्रपति की स्थिति 10.24
- भारत के राष्ट्रपति की वीटो शक्ति 10.27
- भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति 10.31
- भारत और गठबंधन सरकार 10.35

11. संघीय विधानमंडल 11.1-11.78

विधानमंडल की भूमिका 11.1

संगठन 11.1

संरचना एवं चयन पद्धति 11.1
राज्य सभा 11.1
लोक सभा 11.2

अवधि 11.4
राज्य सभा 11.4
लोक सभा 11.4

सदस्यता हेतु अर्हता एवं निरर्हता 11.5
अर्हताएं 11.5
निरर्हताएं 11.5

शपथ या प्रतिज्ञान 11.6

स्थानों की रिक्ति 11.6
दोहरी सदस्यता 11.6
निरर्हता 11.7
पदत्याग 11.8
बिना अनुज्ञा के अनुपस्थिति 11.8
निष्कासन एवं अन्य कारण 11.8

सदस्यों का वेतनादि 11.8

संसद के अधिकारी 11.8
राज्य सभा के पीठासीन अधिकारी 11.8
लोक सभा के पीठासीन अधिकारी 11.9
सचिवालय 11.14
वेतन 11.14

सदन का नेता, प्रतिपक्ष का नेता एवं व्हिप 11.14
सदन का नेता 11.14
प्रतिपक्ष का नेता 11.14
दलीय सचेतक (पार्टी व्हिप) 11.15

कार्य संचालन 11.15
सदन में मतदान 11.15

संसद का सत्र 11.16
सदनों को आहूत करना 11.16
विघटन, सत्रावसान एवं स्थगन 11.16

संसद में भाषा 11.17
संसदीय प्रथाएं/व्यवहार 11.18
गणपूर्ति (कोरम) 11.18
प्रश्नकाल 11.18
शून्यकाल (जीरो आवर) 11.18
आधे घंटे की चर्चा 11.18
अल्पकालीन चर्चा 11.19
प्वाइंट ऑफ ऑर्डर 11.19
विशेष उल्लेख 11.19
प्रस्ताव एवं संकल्प 11.19

संसद की शक्तियां एवं कृत्य 11.24
विधायी 11.24
संवैधानिक 11.24
कार्यपालिका पर नियंत्रण 11.25
वित्तीय 11.25
निर्वाचन संबंधी 11.25
न्यायिक 11.25
अन्य 11.25

संसदीय विशेषाधिकार 11.26
स्रोत 11.26
वैयक्तिक एवं सामूहिक विशेषाधिकार 11.26
सदन का विशेषाधिकार हनन एवं अवमानना 11.28

विधायी प्रक्रिया 11.29
विधेयकों का वर्गीकरण 11.29
साधारण विधेयक 11.29
संयुक्त बैठक 11.33
धन विधेयक 11.34
वित्त विधेयक 11.35
संवैधानिक संशोधन विधेयक 11.36

वित्तीय विधान 11.36
वार्षिक वित्तीय विवरण या केंद्रीय बजट 11.36
वित्त विधेयक 11.37
विनियोग विधेयक 11.37
अनुपूरक एवं अतिरिक्त अनुदान 11.38
अपवादानुदान, प्रत्ययानुदान एवं लेखानुदान 11.38
बजट का अधिनियमन 11.38
रेल बजट का आम बजट के साथ विलय 11.41

सरकार के लिए निधियां 11.42
भारत की संचित निधि 11.42
लोक लेखा 11.42
आकस्मिकता निधि 11.43

संसदीय समितियां 11.43
तर्क/प्रासंगिकता 11.43
भारत में संसदीय समितियों की व्यवस्था 11.43
स्थायी समितियां 11.44
तदर्थ समितियां 11.54

परामर्शदात्री समितियां 11.55
संसदीय मंच 11.56
उत्पत्ति 11.56
उद्देश्य 11.56
संगठन एवं कार्यकाल 11.56

भारतीय संसदीय ग्रुप 11.57
ग्रुप की संरचना एवं प्रबंधन 11.57
लक्ष्य और उद्देश्य 11.57

परिचर्चा

- कार्यपालिका पर संसदीय नियंत्रण 11.58
- भारतीय संसद की स्थितिः शक्तिशाली लेकिन संप्रभु नहीं 11.60
- संसद एवं न्यायपालिका 11.61
- संसद में कोलाहल/हंगामा 11.62
- नेता प्रतिपक्ष का मुद्दा 11.66
- लाभ का पद और संसदीय सचिव 11.69
- राज्य सभा और लोक सभा के बीच तुलना 11.71
- राज्य सभा की प्रासंगिकता 11.73
- राज्य सभा के सभापति की शक्तियों में विस्तार की आवश्यकता 11.76
- राज्य सभा के मनोनीत सदस्यों पर विवाद 11.77

12. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 12.1-12.10

पद का इतिहास 12.1
संवैधानिक एवं संसदीय प्रावधान 12.1
नियुक्ति एवं कार्यकाल 12.2

कैग की स्वतंत्रता की सुनिश्चितता 12.2
भूमिका एवं कार्य 12.2
कैग के प्रतिवेदन 12.4
कैग द्वारा लेखांकन किए जाने वाले निगम 12.5

परिचर्चा

- नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के पद में सुधार की आवश्यकता 12.5
- क्या कैग को बहु-स्तरीय निकाय बना देना चाहिए? 12.8

13. राज्य कार्यकारिणी 13.1-13.15

सामान्य संरचना 13.1
राज्यपाल 13.1
नियुक्ति 13.1
एक नियुक्त राज्यपाल क्यों? 13.1
कार्यकाल 13.2
योग्यता और पद की शर्तें 13.2
परिलब्धियां 13.2
शपथ/प्रतिज्ञान 13.2
शक्तियां और कार्य 13.3
राज्यपाल के विशेषाधिकार 13.6
राज्यपाल का पद 13.6
मंत्रिपरिषद 13.7
मंत्रियों की नियुक्ति और मंत्रालयों का आकार 13.7
पदावधि 13.7
शपथ या प्रतिज्ञान और गोपनीयता की शपथ 13.8
वेतन और भत्ते 13.8
सामूहिक और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 13.8
संगठन एवं कार्य 13.8
मुख्यमंत्री की स्थिति और भूमिका 13.9
महाधिवक्ता 13.10

परिचर्चा

- राज्यपाल की भूमिका पर विवाद 13.11

14. राज्य विधानमंडल 14.1-14.14

संगठन 14.1
संरचना 14.1
विधान सभा 14.1
विधान परिषद 14.2
कार्यकाल 14.3
विधान सभा 14.3
विधान परिषद 14.3
सदस्यता 14.3
अर्हताएं 14.3
संवैधानिक प्रावधान 14.3
संसदीय प्रावधान 14.3
निरर्हताएं 14.3
संवैधानिक प्रावधान 14.3
संसदीय प्रावधान 14.4
दल-बदल विरोधी कानून के तहत निरर्हता 14.4
सीटों की रिक्ति 14.4
शपथ या प्रतिज्ञान 14.5
वेतन 14.5
राज्य विधानमंडल के अधिकारी 14.5
विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 14.5
विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति 14.6
वेतन 14.7
सचिवालय 14.7
कार्य संचालन 14.7
आह्वान, सत्र, स्थगन, सत्रावसान, विघटन 14.7
मतदान एवं गणपूर्ति 14.8
भाषा 14.8
बोलने और मत देने का अधिकार 14.8
राज्य विधानमंडल के कार्य 14.8
विशेषाधिकार 14.8
व्यक्तिगत विशेषाधिकार 14.9
सामूहिक विशेषाधिकार 14.9

विधायी प्रक्रिया 14.10
साधारण विधेयक 14.10
साधारण विधेयक के संबंध में सदन की स्थिति 14.10
राज्यपाल की अनुमति 14.10
राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक 14.11
धन विधेयक 14.12

परिचर्चा

- विधान परिषद की उपयोगिता 14.13

15. स्थानीय स्वशासनः पंचायती राज 15.1-15.15

पंचायती राजः स्वतंत्रता के पश्चात किए गए प्रयासों की समीक्षा 15.1
बलवंत राय मेहता समिति 15.1
अशोक मेहता समिति 15.2
जी.वी.के. राव समिति 15.3
एल.एम. सिंघवी समिति 15.4
थुंगन समिति 15.4
संवैधानिक दर्जा प्रदान करने हेतु किए गए प्रयास 15.5

73वें संशोधन अधिनियम के तहत नए विधान 15.5
त्रिस्तरीय व्यवस्था 15.6
संरचना एवं चयन पद्धति 15.6
सीटों का आरक्षण 15.7
अवधि 15.7
सदस्यों की निरर्हताएं 15.7
शक्तियां और उत्तरदायित्व 15.8
आय के स्रोत 15.8
वित्त आयोग 15.9
लेखाओं की संपरीक्षा 15.9
राज्य निर्वाचन आयोग 15.9
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन 15.10
संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना 15.10

अनुसूचित क्षेत्रों तक पंचायतों का विस्तार (पेसा अधिनियम) 15.10
उद्देश्य 15.10
अधिनियम के प्रावधान 15.11

परिचर्चा

- पंचायती राजः एक आलोचनात्मक अवलोकन 15.12

16. स्थानीय स्वशासनः नगरीय 16.1-16.8

स्थानीय नगरीय शासन 16.1
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 16.1

नगरपालिका के लिए संवैधानिक प्रावधान 16.1
नगरपालिकाओं के प्रकार 16.2
संरचना 16.2
वॉर्ड समितियां 16.2
सीटों का आरक्षण 16.3
अवधि 16.3
सदस्यों के लिए निरर्हताएं 16.3
शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व 16.3
आय के स्रोत 16.4
वित्त आयोग 16.4
लेखा संपरीक्षा 16.4
राज्य निर्वाचन आयोग 16.5
निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन 16.5
संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना 16.5
कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना 16.5
जिला योजना समितियां 16.5
महानगर योजना समितियां 16.5

स्थानीय नगरीय निकायों के प्रकार 16.6
नगर निगम 16.6
नगरपालिका 16.7
अधिसूचित क्षेत्र समिति 16.7
नगर क्षेत्र समिति 16.7
छावनी बोर्ड 16.7
पत्तन न्यास 16.8
टाउनशिप 16.8
विशेष या एकल उद्देश्यीय अभिकरण 16.8

17. सहकारी समितियां 17.1-17.5

सहकारी समितियों की भूमिका 17.1
भारत में सहकारी समितियों का विकास 17.1
सहकारिताओं का वैधानिक तथा संवैधानिक दर्जा 17.1
संविधान (97वां संशोधन) अधिनियम, 2011 17.1
संशोधन के कारण 17.1
प्रावधान 17.2

18. संघ-शासित प्रदेश 18.1-18.8

संघ-शासित प्रदेश 18.1
संघ-शासित प्रदेशों के गठन के कारण 18.1
प्रशासन 18.2
केंद्र की विधायी शक्तियां 18.2
संघ-शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय 18.3
दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान 18.3
जम्मू-कश्मीरः कुछ उल्लेखनीय बिंदु 18.4
सलाहकार समितियां 18.5

परिचर्चा

- केंद्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच सत्ता संघर्ष 18.6
- दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे का मुद्दा 18.7

19. अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्र 19.1-19.7

अनुसूचित क्षेत्र 19.1
अनुसूचित क्षेत्र से क्या अभिप्रेत है? 19.1
प्रशासन हेतु प्रावधान 19.1
पांचवीं अनुसूची में संशोधन 19.2

जनजातीय क्षेत्र 19.2
इन क्षेत्रों का प्रशासन 19.2
स्वायत्त जिले एवं स्वायत्त क्षेत्र 19.3
जिला परिषदें और क्षेत्रीय परिषदें 19.3
अनुसूची का संशोधन 19.7

20. न्यायपालिका और संबंधित मामले 20.1-20.80

संगठन 20.1
उच्चतम न्यायालय 20.2
न्यायाधीशों की नियुक्ति 20.2
शपथ या प्रतिज्ञान 20.3
न्यायाधीश की अर्हताएं 20.3
पदावधि 20.4
न्यायाधीशों की पदच्युति 20.4
वेतन 20.5
रिक्त पद और तदर्थ नियुक्ति 20.5
उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीश 20.6
स्थान 20.6
सुनिश्चित स्वाधीनता 20.6
शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार 20.7
कानूनी सहायता 20.13
एमिकस क्यूरी (न्याय मित्र) के प्रावधान 20.14

उच्च न्यायालय 20.14
न्यायाधीशों की नियुक्ति 20.14
अर्हताएं और शपथ 20.14
वेतन और भत्ते 20.15
कार्यकाल और पदच्युति प्रक्रिया 20.15
न्यायाधीशों का स्थानांतरण 20.15
कार्यकारी न्यायाधीश, अपर न्यायाधीश, सेवानिवृत्त न्यायाधीश 20.16
स्वतंत्रता 20.16
अधिकारिता और शक्तियां 20.17

अधीनस्थ न्यायालय 20.20
संवैधानिक उपबंध 20.20
संगठन एवं शक्तियां 20.20

अधिकरण 20.22
प्रशासनिक अधिकरण 20.22
अन्य मामलों के लिए अधिकरण 20.23
अधिकरणों पर न्यायालय की अधिकारिता 20.23
सशस्त्र बल अधिकरण 20.24
राष्ट्रीय हरित अधिकरण 20.24

विधिक सहायता और विधिक सेवाएं 20.25
विधिक सहायता 20.25
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण 20.25

लोक अदालत 20.26
वैधानिक उपबंध 20.27
स्थायी लोक अदालत 20.28
लोक अदालत योजना के लाभ 20.29

परिवार न्यायालय 20.29
उद्देश्य 20.30
मामलों की प्रकृति एवं प्रक्रिया 20.30

ग्राम न्यायालय 20.31
अधिनियम की मुख्य विशेषताएं 20.31
आलोचनात्मक मूल्यांकन 20.32

फास्ट ट्रैक न्यायालय 20.33
पॉक्सो मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय 20.33
आलोचनात्मक मूल्यांकन 20.34

उपभोक्ता न्यायालय 20.35
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की मुख्य विशेषताएं 20.35

जनहित याचिका 20.46
अवधारणा 20.46
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 20.47
जनहित याचिकाओं की प्रकृति एवं प्रयोजन 20.48
कुछ महत्वपूर्ण पीआईएल मामले 20.51
पीआईएल का उपयोग और दुरुपयोग 20.52

न्याय प्रदायगी एवं विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन 20.54

परिचर्चा

- नियुक्ति एवं उत्तरदायित्व 20.55
- न्यायाधीश और सूचना का अधिकार 20.58
- विलंबित न्याय का मुद्दा 20.60
- क्षमा और दया याचिकाओं पर शक्ति 20.64
- न्यायिक सक्रियता 20.68

21. भारतीय संघवाद 21.1-21.60

संघवाद 21.1
संघवाद की अवधारणा 21.1
संघीय प्रणाली की सरकार की रचना 21.2

भारतीय संघवाद की प्रकृति 21.2
संघीय लक्षण 21.3
एकात्मक लक्षण 21.4
भारतीय संघवादः एक समझौता 21.6

केंद्र-राज्य संबंध 21.8
1. विधायी संबंध 21.8
प्रादेशिक अधिकारिता 21.8
विषयों का वितरण 21.8
राज्य सूची पर संसद की शक्ति का विस्तार 21.10
राज्य कानूनों पर संघ की प्रधान स्थिति 21.11

2. प्रशासनिक संबंध 21.11
कार्यकारी क्षेत्र में केंद्र और राज्य शक्ति की सीमा 21.11
कतिपय मामलों में संघ और राज्य के एक-दूसरे के कार्य प्रत्यायोजित करने की शक्ति 21.12
भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता 21.12
सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां 21.13
राज्यों का सहयोग सुनिश्चित करने में केंद्र की प्रबल स्थिति 21.13

3. वित्तीय विषय 21.13
कर लगाने और करों से प्राप्त राजस्व में हिस्सेदारी संबंधी शक्तियों का वितरण 21.14
गैर-कर राजस्व का वितरण 21.15
राज्यों के हितों का संरक्षण 21.15
सहायता अनुदान 21.16
माल और सेवा कर परिषद 21.16
वित्त आयोग 21.18
अंतर-सरकारी कराधान से छूट 21.19
उधार लेना 21.19
वित्तीय मामलों में केंद्र की सर्वोच्चता 21.19

भारत में संघवाद के कार्यकरण पर राज्य और समितियों की मांग 21.20
विवाद के मुद्दे 21.21
केंद्र-राज्य संबंधों के परीक्षण के प्रयास 21.21
प्रशासनिक सुधार आयोग 21.21
राजमन्नार समिति 21.21
आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 21.22
पश्चिम बंगाल ज्ञापन 21.22
सरकारिया आयोग 21.23
पुंछी आयोग 21.25

अंतरराज्यीय संबंध 21.35
अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल संबंधित विवाद 21.35
संवैधानिक प्रावधान 21.35
संसदीय प्रावधान 21.35
अंतरराज्य परिषदः राज्यों के बीच समन्वय 21.37
संवैधानिक प्रावधान 21.37
आयोग के सुझाव 21.38
अंतरराज्य परिषद की स्थापना 21.38
क्षेत्रीय परिषद 21.38
पूर्वोत्तर परिषद 21.40
अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य 21.41

संविधानेत्तर निकाय और संघवाद 21.42
योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद 21.42
नीति आयोग 21.43
आयोग की स्थापना 21.43
नीति आयोग का औचित्य 21.44
नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत 21.45
नीति आयोग की संरचना 21.46
उद्देश्य 21.46
नीति आयोग का कार्यक्षेत्र 21.47
नीति आयोग के संलग्न/स्वायत्त निकाय 21.48
समालोचना 21.49

परिचर्चा

- सहकारी संघवाद और चुनौतियां 21.50
- प्रतिस्पर्धी संघवाद 21.56
- संघीय व्यवस्था में क्षेत्रवाद का विकास और उसका स्थान 21.58

22. आपात उपबंध 22.1-22.13

आपात उपबंध 22.1
युद्ध, बाह्य आक्रमण, और सशस्त्र विद्रोह के कारण आपात 22.1
प्रावधान 22.1
आधार एवं सीमाएं 22.1
मंत्रिमण्डल का लिखित अनुमोदन 22.2
न्यायिक समीक्षा 22.2
संसद द्वारा अनुमोदन एवं सीमाएं 22.2
आपात की उद्घोषणा की समाप्ति 22.2
संघीय प्रणाली पर प्रभाव 22.3
राज्यों की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य 22.3
मौलिक अधिकारों पर प्रभाव 22.3
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलम्बन 22.4
अभी तक जारी उदघोषणाएं 22.5

राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने पर आपात 22.6
उपबंध 22.6
आधार 22.6
संसदीय अनुमोदन एवं सीमाएं 22.6
उद्घोषणा को समाप्त करना 22.7
प्रभाव 22.7
अनुच्छेद 356 का प्रयोग एवं दुरुपयोग तथा अनुशंसित सुधार 22.8
अनुच्छेद 356 पर संविधान आयोग 22.10
अनुच्छेद 356 पर पुंछी आयोग 22.11
न्यायालय एवं अनुच्छेद 356: न्यायिक समीक्षा 22.11
राष्ट्रपति शासन पर सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देश 22.11

वित्तीय आपात 22.12
प्रावधान 22.12
आधार 22.12
संसदीय अनुमोदन एवं सीमाएं 22.12

उद्घोषणा की समाप्ति 22.13
न्यायिक समीक्षा 22.13
प्रभाव 22.13

23. संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 23.1-23.23

लोक सेवा की भूमिका 23.1
संवैधानिक प्रावधान 23.2
भर्ती एवं सेवा की शर्तें 23.2
संघ या राज्य के सिविल सेवकों की पदावधि 23.2
सिविल सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के लिए रक्षोपाय 23.3
अखिल भारतीय सेवाएं 23.4
अन्य प्रावधान 23.4

लोक सेवाओं का वर्गीकरण एवं कार्यकरण 23.5
अखिल भारतीय सेवाएं 23.5
केंद्रीय सेवाएं 23.5
राज्य सेवाएं 23.7
संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग 23.7
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य 23.7
संवैधानिक एवं अन्य प्रावधान 23.8
नियुक्ति, सेवा-शर्तें और पदावधि 23.8
पदच्युति एवं निलंबन 23.9
आयोगों की स्वायत्तता 23.9
कृत्य एवं दायित्व 23.10
लोक सेवा आयोगों की भूमिका की सीमाएं 23.12

परिचर्चा

- सिविल सेवा सुधारः समस्याएं एवं समाधान 23.13
- लेटरल एंट्री 23.13

24. निर्वाचन एवं निर्वाचन संबंधी विधियां 24.1-24.70

निर्वाचन हेतु संवैधानिक प्रावधान 24.1
संसदीय प्रावधान 24.2
निर्वाचन आयोग 24.2
संरचना 24.2
नियुक्ति, वेतन, पदावधि 24.3
स्वायत्तता 24.3
शक्ति एवं कार्य 24.4

निर्वाचन प्रणाली और निर्वाचनों का संचालन 24.6
निर्वाचन हेतु सीटों तथा निर्वाचन क्षेत्रों का आबंटन 24.6
परिसीमन अधिनियम, 2002 एवं परिसीमन आयोग 24.7
प्रशासनिक तंत्र 24.9
निर्वाचन प्रक्रिया 24.12
संपत्ति एवं देनदारियों की घोषणा 24.19
चुनावी व्यय का ब्यौरा 24.19

निर्वाचन से संबंधित विवाद 24.21
अब तक हुए निर्वाचन 24.22

परिचर्चा

- ईवीएम का मुद्दा 24.28
- आम चुनावों के लिए चुनाव प्रणालियां 24.32
- भारत में आम चुनावों के लिए उपयुक्त एक निर्वाचन प्रणाली 24.37
- भारत में मतदान व्यवहार 24.42
- अनिवार्य मतदान का मुद्दा 24.49
- निर्वाचित प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार 24.52
- क्या भारत में जनमत संग्रह होना चाहिए? 24.56
- पंचायत चुनावों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का मुद्दा 24.63
- संसद और राज्य विधान सभाओं के समकालिक चुनाव का मुद्दा 24.64

25. राजनीतिक दल एवं दबाव समूह 25.1-25.22

राजनीतिक दल का अर्थ 25.1
राजनीतिक दलों का वर्गीकरण 25.1
कैडर-आधारित तथा जन-आधारित 25.1
विचारधारा के आधार पर 25.2
अन्य समूह 25.2

दलीय व्यवस्था 25.3
एक-दलीय व्यवस्था 25.3

द्वि-दलीय व्यवस्था 25.3
बहुदलीय व्यवस्था 25.4
लाभ 25.4
हानि 25.4
अनिवार्य रूप से अस्थिर सरकार नहीं 25.4
देश की दलीय व्यवस्था कैसे निर्धारित होती है 25.5

राजनीतिक दलों का महत्व एवं कार्य 25.5
दोष 25.6

भारत में दलीय व्यवस्था 25.6
उद्विकास एवं प्रवृत्ति 25.6
भारत की दलीय व्यवस्था के अभिलक्षण 25.7
उपसंहार 25.9

राजनीतिक दलों के लिए निर्वाचन आयोग के मापदंड 25.10
राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का मापदंड 25.11
एक राज्य दल के रूप में मान्यता के लिए मापदंड 25.11
पंजीकरण एवं मान्यता के लाभ 25.12

क्षेत्रीय दल 25.12
क्षेत्रीय दलों का प्रसार 25.12
क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण 25.13
क्षेत्रीय दलों के अभिलक्षण 25.13
भूमिका एवं महत्व 25.14

दल-बदल विरोधी कानून और राजनीतिक दल 25.15
दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान 25.15
समालोचनात्मक मूल्यांकन 25.16

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह 25.18

परिचर्चा

- राजनीतिक दल तथा आरटीआई 25.20

26. चुनाव संबंधी सुधार 26.1-26.28

विभिन्न समितियां और उनकी सिफारिशें 26.1
जस्टिस तारकुंडे समिति 26.1
दिनेश गोस्वामी समिति 26.1
इंद्रजीत गुप्ता समिति 26.2
राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग की सिफारिशें 26.3
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 26.4
विधि आयोग के सुझाव 26.4

चुनावी सुधार हेतु उठाए गए कदम 26.5
चुनाव संबंधी अधिक सुधारों की आवश्यकता 26.14
निर्वाचन प्रणाली में सुधार 26.14
निर्वाचन आयोग को प्रभावित करने वाले सुधार 26.14
निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार 26.15
भ्रष्टाचार एवं अपराधमुक्त निर्वाचन सुनिश्चित करने हेतु सुधार 26.15
धनबल पर नियंत्रण 26.16
राजनीतिक दलों और राजनीतिक जवाबदेही में अपेक्षित सुधार 26.16

परिचर्चा

- भारत में चुनावी निधिकरण 26.17
- एक्जिट पोल तथा ओपिनियन पोल 26.26

27. भाषाएं 27.1-27.11

संघ की भाषा 27.1
राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति 27.1
राजभाषा अधिनियम, 1963 27.1

प्रादेशिक भाषाएं 27.3
राज्य की राजभाषा/राजभाषाएं 27.3
संघ-राज्य और अंतरराज्यीय संप्रेषण की भाषा 27.4
किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध 27.4

न्यायालयों, अधिनियमों और नियमावलियों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा 27.5
न्यायालयों की भाषा 27.5
विधेयकों, अधिनियमों और नियमों की भाषा 27.5

विशेष निर्देश 27.6
भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (या आयुक्त) 27.6

संवैधानिक प्रावधान 27.6
पद का सृजन 27.7
परिकल्पना विवरण और लक्ष्य 27.7
उद्देश्य 27.7
कार्य 27.7

शास्त्रीय भाषा का दर्जा 27.8

परिचर्चा

- भाषा की राजनीति 27.9

28. कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध 28.1-28.8

विशेष उपबंधों का आधार 28.1
अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां 28.1
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का विनिर्दिष्टीकरण 28.1
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रावधान 28.1
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 28.3
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 28.4
पिछड़ा वर्ग 28.5
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 28.6
आंग्ल-भारतीय 28.8
विनिर्देश 28.8
उपबंध 28.8

29. अल्पसंख्यक 29.1-29.9

सांविधानिक प्रावधान 29.1
अधिकारों के साझा एवं पृथक अधिकार क्षेत्र 29.1
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 29.2
अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम 29.2
भारत में मुसलमानों पर सच्चर समिति की रिपोर्ट 29.4
कुंडू समिति–सच्चर समिति के पश्चात की मूल्यांकन रिपोर्ट 29.5
राष्ट्रीय धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट 29.9

30. कतिपय राज्यों हेतु विशेष उपबंध 30.1-30.5

जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित अनुच्छेद 370 की प्रास्थिति 30.1
महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध 30.1
नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 30.2
असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 30.3
मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 30.3
आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 30.3
सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 30.4
मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 30.4
अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 30.4
गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 30.5
कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध 30.5

31. सरकार के अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं 31.1-31.6

कुछ एवं अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों, एवं बाध्यताओं का उत्तराधिकार 31.1
राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति 31.1
राज्यक्षेत्रीय सागर खंड/महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजें 31.1
संपत्ति का अर्जन, व्यापार करने इत्यादि की शक्ति 31.2
संविदाएं और सरकारी दायित्व 31.2
वाद और कार्यवाहियां 31.2
संप्रभु उन्मुक्ति का मामला 31.2
न्यायिक निर्णय 31.3
विधि निर्माण की जरूरत 31.5
वाद के खिलाफ लोक अधिकारियों की उन्मुक्ति 31.5

32. संविधान संशोधन एवं इसके आधारिक लक्षण **32.1-32.11**

अनम्य एवं नम्य संविधान 32.1
संशोधन प्रक्रियाओं के प्रतिमान 32.1
भारत में संशोधन प्रक्रिया 32.3
नम्यता एवं अनम्यता का संयोजन 32.3
संशोधन की प्रक्रिया 32.3
संशोधन के प्रकार 32.4
आलोचनात्मक बिंदु 32.5
संसद की संशोधन शक्ति की सीमा और आधारिक लक्षण 32.6
संविधान की संशोधनीयता और बुनियादी सरंचना की अवधारणा का विकास 32.6
बुनियादी लक्षणों का सिद्धांत–विकास 32.7
मूल संरचना की अवधारणा की आलोचना और समर्थन 32.10

33. संविधान की अनुसूचियां **33.1-33.4**

अनुसूचियां 33.1
पहली अनुसूची 33.1
दूसरी अनुसूची 33.1
तीसरी अनुसूची 33.2
चौथी अनुसूची 33.3
पांचवीं अनुसूची 33.3
छठी अनुसूची 33.3
सातवीं अनुसूची 33.3
आठवीं अनुसूची 33.3
नौवीं अनुसूची 33.3
दसवीं अनुसूची 33.4
ग्यारहवीं अनुसूची 33.4
बारहवीं अनुसूची 33.4

34. शक्तियों का पृथक्करण **34.1-34.11**

अवधारणा 34.1
व्यवहार में शक्तियों का पृथक्करण 34.2
संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 34.2
यूनाइटेड किंगडम की प्रणाली 34.3
ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक व्यवस्था 34.4
फ्रांस की राजनीतिक प्रणाली 34.5
भारत और शक्तियों का पृथक्करण 34.5
शक्तियों का सीमित पृथक्करण और निश्चित सीमा में अधिव्यापन 34.5
कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध एवं दलों की भूमिका 34.6
भारत में शक्तियों के पृथक्करण के विशेष लक्षण 34.7
विवाद निवारण तंत्र और संस्थान 34.8
मध्यस्थ के रूप में उच्चतम न्यायालयः विधायी और कार्यकारी क्षेत्रों में अतिक्रमण का मुद्दा 34.9

35. संविधिक, नियामक, अर्द्ध-न्यायिक तथा अन्य निकाय **35.1-35.54**

विभिन्न प्रकार के संगठनों की प्रकृति 35.1
संवैधानिक निकाय 35.1
संविधिक निकाय 35.1
विनियामक निकाय 35.2
अर्द्ध-न्यायिक निकाय 35.2
गैर-संवैधानिक और गैर-संविधिक निकाय 35.3
विशिष्ट संविधिक और विनियामक निकाय 35.3
1. अधिकार संबंधी निकाय 35.3
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग 35.3
राज्य मानव अधिकार आयोग 35.8
मानव अधिकार न्यायालय 35.10
राष्ट्रीय महिला आयोग 35.11
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 35.14
केंद्रीय सूचना आयोग 35.16
राज्य सूचना आयोग 35.18
2. सतर्कता एवं भ्रष्टाचार-निरोधक निकाय 35.21
लोकपाल 35.21
लोकायुक्त 35.31
केंद्रीय सतर्कता आयोग 35.32

3. संरक्षा-संबंधित निकाय 35.39
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण 35.39
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 35.42
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 35.44
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 35.45

4. मीडिया संबंधित निकाय 35.46
भारतीय प्रेस परिषद 35.46
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड 35.48

गैर-संवैधानिक एवं गैर-संविधिक निकाय 35.50
विधि आयोग 35.50
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 35.51

36. भारत की विदेश नीति 36.1-36.11

विदेश नीति के निर्धारक तत्व 36.1
भारत में विदेश नीति के सिद्धांत 36.1
विभिन्न वर्षों में विदेश नीति 36.3
भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्य 36.6
भारत और वैश्विक/क्षेत्रीय संगठन 36.7

37. भारतीय संविधान की कार्यप्रणाली 37.1-37.14

राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग 37.1
एनसीआरडब्ल्यूसी के सदस्य 37.1
आयोग के विचारार्थ विषय 37.2
कार्यकाल 37.2
आयोग की रिपोर्ट 37.2
संविधान की कार्यप्रणाली पर समग्र दृष्टिकोण 37.2
चिंता के क्षेत्र 37.4
अनुशंसाएं 37.5

परिशिष्ट प.1.1-प.1.51

1. राजनीतिक शब्दावली प.1
2. विधायी शक्तियों का विभाजन प.7
3. राष्ट्रीय प्रतीक प.14
4. मुख्य पदाधिकारी (दिसम्बर 2022 तक) प.17
   I. भारत के राष्ट्रपति प.17
   II. भारत के उपराष्ट्रपति प.17
   III. भारत के प्रधानमंत्री प.17
   IV. भारत के उपप्रधानमंत्री प.17
   V. लोक सभा अध्यक्ष प.18
   VI. भारत के मुख्य न्यायाधीश प.18
   VII. भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त प.18
   VIII. वित्त आयोग के अध्यक्ष प.19
   IX. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष प.19
   X. भारत के महान्यायवादी प.19
   XI. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प.20
   XII. चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प.20
   XIII. थल सेनाध्यक्ष प.20
   XIV. नौसेना अध्यक्ष प.20
   XV. वायु सेनाध्यक्ष प.21
   XVI. विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख (दिसम्बर 2022 तक) प.21
5. संसद में राज्यों/संघ प्रदेशों का प्रतिनिधित्व प.22
6. विधान सभाओं और विधान परिषदों में सदस्यता प.23
7. लोक सभाः मतदान और कार्यकाल प.24
8. उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एवं अवस्थान प.25
9. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठों की क्षेत्रीय अधिकारिता प.26
10. विभिन्न लोक सभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व प.26
11. भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग प.27
12. कुछ विशिष्ट कार्यकारियों/अधिकारियों के वेतन प.28
13. संवैधानिक संशोधन प.28
14. महत्वपूर्ण अधिनियम प.39
    जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 प.39
    जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2021 प.42
    जम्मू एवं कश्मीर राजभाषा अधिनियम, 2020 प.42
    निर्वाचन विधि (संशोधन) अधिनियम, 2021 प.43
    राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 प.45
    आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रधानमंत्री का का दस सूत्रीय एजेंडा प.46
    सतानवें संविधान (संशोधन) अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय प.47
    उच्चतम न्यायालय द्वारा 103वें संवैधानिक संशोधन का समर्थन प.48
    नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) प.51